GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO - 83
ANSWERED ON - 09/02/2022

USE OF DRUGS AMONG WOMEN AND CHILDREN

83. SHRI M.V. SHREYAMS KUMAR

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) whether Government has noted that the incidence of use of drugs is rising rapidly among women and children in the country;

(b) if so, the details thereof, and the steps proposed by Government to control it;

(c) the number of women and children detained for selling/using drugs during each of the last three years and the current year; and

(d) the details of financial assistance provided to de-addiction centres during the said period, State-wise?

ANSWER

MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DR. VIRENDRA KUMAR)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

*****

Statement in reply to Rajya Sabha Starred Question *83 for answer on 09.02.2022 by Shri M. V. Shreyams Kumar on "Use of drugs among women and children"

(a) and (b) As per the National Survey on Extent and Pattern of Substance Use in India conducted during 2018, the details of drug abuse among children and women is as under:

Substance	Prevalence of current use			
	Children (10-17 Years)	Estimated no. of Users	Women (10-75 years)	Estimated no. of Users
Cannabis	0.92%	20,00,000	0.65%	3480000
Opioids	1.78%	40,00,000	0.16%	853000
Sedatives	0.58%	20,00,000	0.11%	567000
Cocaine	0.06%	2,00,000	0.02%	91000
ATS	0.18%	4,00,000	0.05%	268000
Inhalants	1.17%	30,00,000	0.08%	429000
Hallucinogens	0.07%	2,00,000	0.01%	54000

To address the problem of Drug Abuse among children and women, Ministry of Social Justice and Empowerment has formulated and implemented National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) under which the Government is taking a sustained and coordinated action for arresting the problem of substance abuse among the youth and women. This includes:

i. Launched Nasha Mukt Bharat Abhiyaan (NMBA) in 272 most vulnerable districts under which a massive community outreach is being done through more than 8000 youth volunteers. More than 47 Lakh youth, 29.5 Lakh women have been reached out so far.

ii. 356 Integrated Rehabilitation Centres for Addicts (IRCAs) are supported by the Ministry. These IRCAs not only provide for treating the drug victims, but also give services of preventive education, awareness generation, motivational counselling, detoxification/de-addiction, after care and re-integration into the social mainstream. Ministry also provided support to special de-addiction centre for women and children.

iii. 53 Community based Peer led Intervention (CPLI) Centres are supported by the Ministry. These CPLIs focus on vulnerable and at risk children and adolescents. Under this, peer educators engage children for awareness generation and life skill activities.

iv. 78 Outreach and Drop In Centres (ODICs) are supported by the Ministry. These ODICs provide safe and secure space of treatment and rehabilitation for substance users, with provision of screening, assessment and counselling and thereafter provide referral and linkage to treatment and rehabilitation services for substance dependence.

v. Ministry also supports setting up of 36 Addiction Treatment Facilities (ATFs) in some Government hospitals, which is being implemented through AIIMS, New Delhi.

vi. A Toll-free Helpline for de-addiction, 14446 is being maintained by the Ministry for providing primary counseling and immediate assistance to the persons seeking help through this helpline.

vii. Ministry through its autonomous body National Institute of Social Defence (NISD) and other collaborating agencies like SCERTs, Kendriya Vidyalaya Sangathan etc. provides for regular awareness generation and sensitization sessions for all stakeholders including students, teachers, parents. So far, 1,67,042 persons have been sensitized through these programmes in the last 2 years and current financial year.

(c) No gender and age-wise arrest details are being received from Centre and State DLEAs. However, the detail of total person arrested under NDPS Act for the last three years and current years as reported are mentioned below:

2018 : 60,155
2019 : 74,620
2020* : 67,214
2021*(Sep. 2021) : 43,179

*Data is provisional

(d) The details of financial assistance provided to these centres during last three years and the current year, State-wise is placed at **Annexure-I.**

*****

Annexure-I

State-wise details of funds released to De-addiction centres

(Rupees in lakhs)

	States/UTs	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (till 03.02.2022)
1	A&N islands	0	0	0	0
2	Andhra Pradesh	302.45	314.41	394.2	241.88
3	Arunachal Pr.	0	2.32	0	0
4	Assam	469.37	333.68	668.51	287.25
5	Bihar	197.53	105.12	396.91	116.16
6	Chandigarh	0	0	15.79	24.11
7	Chhatisgarh	17.76	39.14	88.10	60.07
8	D&N Haveli	0	0	0	0
9	Daman &Diu	2.2	0	17.74	19.87
10	Delhi	241.5	267.39	392.03	302.93
11	Goa	0	0	0	0
12	Gujarat	145.65	215.86	169.66	132.30
13	Haryana	157.05	166.31	247.00	87.37
14	Himachal Pradesh	34.35	53.52	39.56	64.19
15	Jammu &Kashimir	20.04	18.99	84.28	41.81
16	Jharkhand	0	2.2	39.18	11.06
17	Karnataka	698.11	1290.08	922.11	429.15
18	Kerala	307.44	905.13	596.37	217.58
19	Lakshadweep	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	252.05	270.37	479.63	210.89
21	Maharashtra	1370.7	1645.7	1790.38	410.94
22	Manipur	545.01	864.2	634.09	406.22
23	Meghalaya	14.13	58.49	11.90	0
24	Mizoram	265.96	212.76	216.62	116.88
25	Nagaland	179.3	155.74	140.00	122.93
26	Orissa	846.31	1115.06	1066.39	627.76
27	Puducherry	81.16	41.36	66.37	22.21
28	Punjab	96.52	167.04	154.92	60.50
29	Rajasthan	177.91	498.28	658.63	220.90
30	Sikkim	38.18	18.55	41.58	22.26
31	Tamil Nadu	838.09	750.8	566.43	316.35
32	Telangana	123.06	351	244.79	135.48
33	Tripura	0	2.45	7.75	7.77
34	Uttar Pradesh	374.63	510.7	1049.44	295.71
35	Uttarakhand	55.12	213.23	38.65	57.39
36	West Bengal	94.16	236.53	213.84	96.90
	Total	**7945.74**	**10826.41**	**11452.85**	**5166.82**

*****

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *83

उत्तर देने की तारीखः 09.02.2022

महिलाओं और बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जाना

***83. श्री एम. वी. श्रेयम्स कुमार:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि देश में महिलाओं और बच्चों द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किए जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में नशीले पदार्थों की बिक्री/सेवन करने के लिए कितनी-कितनी महिलाओं और बच्चों को हिरासत में लिया गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान नशामुक्ति केंद्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेन्द्र कुमार)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 09.02.2022 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *83 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) वर्ष 2018 के दौरान, भारत में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की सीमा तथा पैटर्न के संबंध में किए गए राष्ट्रीय व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार, बच्चों तथा महिलाओं में ड्रग के दुरूपयोग का ब्यौरा निम्नवत है:-

पदार्थ का नाम	वर्तमान उपयोग की व्यापकता			
	बच्चे (10-17 वर्ष)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या	महिलाएं (10-75 वर्ष)	उपयोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या
कैनबिस	0.92%	20,00,000	0.65%	3480000
ओपिओइड	1.78%	40,00,000	0.16%	853000
सिडेटिव	0.58%	20,00,000	0.11%	567000
कोकीन	0.06%	2,00,000	0.02%	91000
एटीएस	0.18%	4,00,000	0.05%	268000
इनहेलेंट्स	1.17%	30,00,000	0.08%	429000
हैलुसिनोजन	0.07%	2,00,000	0.01%	54000

बच्चों तथा महिलओं में ड्रग के दुरूपयोग की समस्या का समाधान करने के लिए, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने ड्रग की मांग में कटौती करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीडीडीआर) बनाकर कार्यान्वित की है जिसके अंतर्गत सरकार युवाओं तथा महिलाओं में नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की समस्या की रोकथाम करने के लिए एक सतत् तथा समन्वित कार्रवाई कर रही है। इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

i. देश के सर्वाधिक असुरक्षित 272 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरूआत की गई है जिसके अंतर्गत 8000 से अधिक युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से एक व्यापक सामुदायिक पहुंच बनाई जा रही है। अब तक 47 लाख से अधिक युवाओं तथा 29.5 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंच बनाई गई है।

ii. मंत्रालय द्वारा 356 एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) की सहायता की गई है। ये आईआरसीए केन्द्र न केवल ड्रग पीड़ितों के लिए उपचार उपलब्ध कराते हैं बल्कि निवारक शिक्षा, जागरूकता सृजन, प्ररेक परामर्श, नशानिवारण/नशामुक्ति उतरवर्ती देखभाल तथा समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल करने से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष नशामुक्ति केन्द्रों को भी सहायता प्रदान करता है।

-२-

iii. मंत्रालय द्वारा 53 समुदाय आधारित संगतिपरक इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केन्द्रों की भी सहायता की जाती है। ये सीपीएलआई केन्द्र के अंदर असुरक्षित तथा जोखिम ग्रस्त बच्चों तथा किशोरों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं इसके अंतर्गत, साथी शिक्षक बच्चों को जागरूकता सृजन तथा जीवन कौशल क्रियाकलापों में लगाते हैं।

iv. मंत्रालय द्वारा 78 आउटरीच तथा ड्राप इन केन्द्रों (ओडीआईसी) की सहायता की जाती है। ये ओडीआईसी केन्द्र नशीले पदार्थों के व्यसनियों के लिए सुरक्षित उपचार तथा पुनर्वास स्थान उपलब्ध कराते हैं जिनमें जांच, मूल्यांकन तथा परामर्श का प्रावधान होता है तथा इसके बाद नशीले पदार्थों पर निर्भर व्यक्तियों के उपचार तथा पुनर्वास के लिए रेफैल तथा लिंकेज सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

v. मंत्रालय कुछ सरकारी अस्पतालों में 36 व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) की स्थापना करने में भी सहायता कर रहा है जिन्हें एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

vi. मंत्रालय द्वारा नशामुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नं. 14446, हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों के लिए प्राथमिक परामर्शी तथा तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है।

vii. मंत्रालय अपने स्वायत निकाय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियां जैसे एससीईआरटी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन आदि के माध्यम से छात्रों, अध्यापकों तथा माता-पिताओं सहित सभी हितधारकों के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन तथा संवेदनशील सत्र आयोजित करता है। अब तक 1,67,042 व्यक्तियों को गत 2 वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील किया गया है।

(ग) केन्द्र तथा राज्यों के डीएलईएएस से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में कोई लिंगवार तथा आयुवार ब्यौरे प्राप्त नहीं होते हैं। तथापि, गत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कुल व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

2018 : 60,155
2019 : 74,620
2020* : 67,214
2021*(सितम्बर 2021) : 43,179

*यह आंकडा अनंतिम है।

(घ) गत 3 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है:-

-3-

अनुबंध-I

नशामुक्त केन्द्रों को जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (03.02.2022 तक)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	302.45	314.41	394.2	241.88
3	अरुणाचल प्रदेश	0	2.32	0	0
4	असम	469.37	333.68	668.51	287.25
5	बिहार	197.53	105.12	396.91	116.16
6	चंडीगढ़	0	0	15.79	24.11
7	छत्तीसगढ़	17.76	39.14	88.10	60.07
8	दादर व नागर हवेली	0	0	0	0
9	दमन और दीव	2.2	0	17.74	19.87
10	दिल्ली	241.5	267.39	392.03	302.93
11	गोवा	0	0	0	0
12	गुजरात	145.65	215.86	169.66	132.30
13	हरियाणा	157.05	166.31	247.00	87.37
14	हिमाचल प्रदेश	34.35	53.52	39.56	64.19
15	जम्मू और कश्मीर	20.04	18.99	84.28	41.81
16	झारखंड	0	2.2	39.18	11.06
17	कर्नाटक	698.11	1290.08	922.11	429.15
18	केरल	307.44	905.13	596.37	217.58
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	252.05	270.37	479.63	210.89
21	महाराष्ट्र	1370.7	1645.7	1790.38	410.94
22	मणिपुर	545.01	864.2	634.09	406.22
23	मेघालय	14.13	58.49	11.90	0
24	मिजोरम	265.96	212.76	216.62	116.88
25	नागालैण्ड	179.3	155.74	140.00	122.93
26	ओडिशा	846.31	1115.06	1066.39	627.76
27	पुदुचेरी	81.16	41.36	66.37	22.21
28	पंजाब	96.52	167.04	154.92	60.50
29	राजस्थान	177.91	498.28	658.63	220.90
30	सिक्किम	38.18	18.55	41.58	22.26
31	तमिलनाडु	838.09	750.8	566.43	316.35
32	तेलंगाना	123.06	351	244.79	135.48
33	त्रिपुरा	0	2.45	7.75	7.77
34	उत्तर प्रदेश	374.63	510.7	1049.44	295.71
35	उत्तराखंड	55.12	213.23	38.65	57.39
36	पश्चिम बंगाल	94.16	236.53	213.84	96.90
	कुल	**7945.74**	**10826.41**	**11452.85**	**5166.82**

*****

SHRI M. V. SHREYAMS KUMAR: Sir, there are so many NGOs and voluntary organizations working in the drug addiction field and Government sponsored programmes in various institutions. But still drug abuse is spreading in a big way. Many cases have been filed by Narcotics Department. Will the Government try to find more effective ways to deal with the problem?

SHRI A. NARAYANASWAMY: The National Survey on Extent and Pattern of Substance Use in India conducted a survey in 2018. A 'National Survey on Extent, Pattern and Trends of Substance Use' (2004) commissioned by the Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE) was conducted in collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The household survey component of the 2004 study reported that the prevalence of 'current' use of Alcohol was 21 per cent, Cannabis three per cent and Opiates 0.7 per cent among men aged 12-60 years. Among the current users, about 26 per cent of alcohol users were reported to be dependent, while 25 per cent of cannabis users..

SHRI JOHN BRITTAS: That is not the question, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. I have already explained the process. If you are not satisfied with the answer, please follow that.

SHRI A. NARAYANASWAMY: We have taken many steps. We have started Navachaithanya models for generating awareness about ill effects of substance abuse. We have done a number of Nasha Mukt Bharat Abhiyaans (NMBA) in the country. We have Navachaithanya programme for school children between the ages of 11 and 18 years. We have Navachaithanya one days' awareness generation preventive education programme for school children for classes between six and eight. The programme for the awareness for all the schools of children of...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. Question Hour is over.